दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेज़ी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विज़िट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 23 दिसंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 86

डीआरडीओ ने अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक बेहद अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत को रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी मजबूती दी है। डीआरडीओ ने बुधवार को ओडिशा तट के पास कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम है 'प्रलय'। डीआरडीओ ने जारी एक बयान में बताया, भारत ने ओडिशा तट के पास कम दूरी की, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम निर्देशित बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' का सफल परीक्षण किया।

डीआरडीओ द्वारा विकसित यह ठोस-ईंधन, बैटलफील्ड मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है। सूत्रों ने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब साढ़े दस बजे प्रक्षेपित की गई मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। प्रलय 350-500 किमी कम दूरी की, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500-1,000 किलोग्राम है।

राफेल डील में देरी बर्दाश्त नहीं, भारत ने ऑफसेट में देरी के लिए दसॉल्ट पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत ने 36 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 7.8 अरब यूरो के सौदे में ऑफसेट प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में देरी के लिए जुर्माना लगाया है। डिफ़ॉल्ट आयुध की बड़ी कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए बनायी गई नई नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने कहा कि मिसाइल निर्माता एमबीडीए से जुर्माना लगाया गया है, जो दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल जेट के लिए हथियार पैकेज आपूर्तिकर्ता है। भारत ने फ्रांस के साथ समझौते और हथियारों के लिए आपूर्ति प्रोटोकॉल के अलावा, दसॉल्ट के साथ एक बड़ा ऑफसेट अनुबंध और अपने सहयोगी एमबीडीए के साथ एक छोटा अनुबंध भी किया था। सौदे के तहत, अनुबंध मूल्य का 50प्रतिशत (लगभग 30,000 करोड़ रुपये) भारत को ऑफसेट या पुनः निवेश के रूप में वापस गिरवी रखना होगा। एमबीडीए पर सितंबर 2019-सितंबर 2020 से पहले लागू वर्ष के लिए अपने ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन करने में चूक के बाद जुर्माना लगाया गया है।

कैग की रिपोर्ट में भी की गई थी आलोचना- सीएजी की एक रिपोर्ट ने इस तथ्य की आलोचना की थी कि राफेल सौदे में ऑफसेट का अधिकतम निर्वहन - एमबीडीए द्वारा 57प्रतिशत और दसॉल्ट द्वारा 58प्रतिशत - केवल सातवें वर्ष (2023) के लिए निर्धारित है।

हंगामे और गतिरोध के बीच संसद का शीत सत्र खत्म

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दो दिन बचे थे, लेकिन हंगामे और गतिरोध के चलते आज संसद शुरू होते ही दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सदन न चल पाने को लेकर नाराजगी जताई और सांसदों से कहा कि सदन अपनी क्षमता के मुकाबले बहुत कम चली। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप आत्मावलोकन करें कि इस सदन में काम कितना बेहतर हो सकता था। मेरा इस पर बहुत आलोचनात्मक नजरिया है।

उधर, तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन कल निलंबित कर दिए गए थे, जिसके बाद आज वो संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 निलंबित सांसदों के धरने में शामिल हुए। डेरेक पर सदन की रूल बुक फाड़ने का आरोप लगा है। हालांकि, उन्होंने इससे इनकार किया है।

बता दें कि सरकार ने कल लोकसभा में स्मृति ईरानी ने लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव पेश किया था। वहीं, निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद विपक्ष के विरोध के बीच इसे कल राज्यसभा में पेश किया गया था। शीतकालीन सत्र के आखिरी सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसदीय दल की बैठक भी हुई थी।

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कई विधेयकों को पारित कराने में सफल साबित हुई। सत्र की शुरुआत में ही कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल पर मुहर लगाई गई। वहीं, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने संबंधी चुनाव सुधार बिल, जजों के वेतन-भत्ते व सेवा शर्तें, एनडीपीएस बिल, सीबीआई-प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने और जननीय प्रजनन उपचार उद्योग विनियमन बिल को संसद से मंजूरी मिली।

महत्वपूर्ण एवं खास

कर्नाटक में महसूस किए गए मामूली तीव्रता के भूकंप के झटके

चिक्कबल्लापुरा (आरएनएस)। बेंगलुरू के पड़ोसी जिले चिक्कबल्लापुर में बुधवार सुबह दो मामूली तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होने के बाद चिक्कबल्लापुर तालुक के घबराए ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) ने कहा कि 3.1 और 3.3 तीव्रता के भूकंप बेंगलुरु से 66 किलोमीटर दूर चिक्कबल्लापुर क्षेत्र में आए। एनसीएस के अनुसार, पहला भूकंप सुबह करीब 7.09 बजे और दूसरा सुबह 7.14 बजे आया। भूकंप शेट्टी गेरे गांव के बिसेगारहल्ली में महसूस किया गया। चिंतामणि और मांडिकल तालुक के गांवों ने भी भूकंप का अनुभव किया। चिक्कबल्लापुर जिले के बागपल्ली तालुक में आखिरी बार 2018 में 3.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।

निलंबित सांसदों के साथ विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर पढ़ी संविधान की प्रस्तावना

नई दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद विपक्षी नेताओं ने निलंबित सांसदों के समर्थन में संसद के बाहर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। बाद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी नेताओं ने निलंबित सांसदों के साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और सांसदों के निलंबन के विरोध में संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने राष्ट्गान का पाठ किया। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में कांग्रेस व टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था। इन सदस्यों को मॉनसून सत्र के दौरान ''अशोभनीय आचरण'' करने के कारण, शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था।

पाकिस्तान से तुर्की तक चलेगी मालगाड़ी, 10 साल के बाद फिर से हुई शुरुआत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को जोड़ने वाली एक मालगाड़ी सेवा क्षेत्रीय संपर्क में सुधार और तीनों देशों के बीच व्यापार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए फिर से शुरू की गई है। यह सेवा, 10 से अधिक वर्षों तक निलंबित रही। तीनों देशों पाकिस्तान, तुर्की और ईरान की योजना भविष्य में इसी मार्ग पर एक यात्री रेल सेवा शुरू करने की भी है। पाकिस्तान के रेल मंत्री आजम खान स्वाति ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और प्रधानमंत्री के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद के साथ मंगलवार को यहां मार्गल्ला रेलवे स्टेशन पर इस्लामाबाद-तेहरान-इस्तांबुल (आईटीआई) मालगाड़ी शुरू की। इस अवसर पर तुर्की, ईरान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राजदूत भी मौजूद थे। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईटीआई मालगाड़ी का हर परिचालन होगा जो इस्लामाबाद में मार्गल्ला रेलवे स्टेशन से अपना सफर शुरू करके ईरान के जाहेदन में पहली मंजिल की तरफ बढ़ेगी और फिर इस्तांबुल जाएगी।

ओमिक्रॉन की राजधानी बन रही दिल्ली, महाराष्ट्र में भी ज्यादा हुए केस दर्ज, देश भर से आए कुल 213 मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के अब कुल 213 केस हैं और सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली में हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में अब तक महाराष्ट्र आगे था लेकिन दिल्ली ने अब उसे पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई राज्यवार ओमिक्रॉन मरीजों की सूची के मुताबिक, अब दिल्ली में इस वैरिएंट के सबसे ज्यादा 57 केस हैं और महाराष्ट्र में 54 मामले।

नई सूची के मुताबिक, दिल्ली के 57 ओमिक्रॉन मरीजों में से 17 अब ठीक हो चुके हैं। वहीं, महाराष्ट्र में भी वायरस से संक्रमित 28 लोग अब स्वस्थ हो गए हैं। इन दोनों के बाद तेलंगाना सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन केसों के मामले में तीसरे नंबर पर है। यहां 24 ओमिक्रॉन संक्रमित हैं, जिनमें से किसी को भी अभी छुट्टी नहीं मिली है। इसके अलावा कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, जम्मू-कश्मीर में 3, ओडिशा में 2, उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, तमिलाडु में 1 और पश्चिम बंगाल में भी 1 मामले दर्ज किए गए हैं।

कुल 213 ओमिक्रॉन पॉजिटिवों में से अब तक 90 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच भारत में कोरोना के 6317 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि, इस दौरान कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही है।

उत्तरप्रदेश में जेल से भागने की कोशिश में कैदी की हुई मौत

अलीगढ़ (आरएनएस)। हत्या के आरोप में गिरफ्तार एक युवक की अलीगढ़ जिला जेल में कथित तौर पर मैनहोल से भागने की कोशिश में मौत हो गयी। मंगलवार को कैदी का शव मैनहोल से बरामद किया गया। हालांकि, जेल अधिकारियों ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि उसने आत्महत्या कर ली होगी। 24 वर्षीय व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसकी मौत की जानकारी सीसीटीवी फुटेज से सामने आई, जब जेल अधिकारियों ने उसे कैदियों की गिनती के दौरान परिसर में नहीं पाया। वीडियो में वह मैनहोल के पास खड़ा नजर आ रहा था और कुछ सेकेंड बाद वह चुपचाप उसमें घुस गया। जेल अधिकारियों ने कहा कि मैनहोल में एक नाला है जो जेल की दीवारों के नीचे है और परिसर के बाहर खुलता है। मैनहोल के ढक्कन को खुला छोड़ दिया गया था क्योंकि इसकी सफाई निर्धारित थी।

24 वर्षीय मोनू कुमार हाथरस का रहने वाला था और एक महिला की हत्या के आरोप में 13 नवंबर से अलीगढ़ जिला जेल में बंद था। जिला कारागार के जेलर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को उसकी सुनवाई होनी थी। उन्होंने कहा कि गिनती के समय, वह लापता पाया गया था। जब हम उसे कहीं नहीं ढूंढ पाए, तो हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और उसे बैरक के पीछे मैनहोल में प्रवेश करते हुए पाया।

उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही कैदी को मैनहोल से बाहर लाया गया, डॉक्टरों को बुलाया गया और उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल अधीक्षक मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी उनके परिवार को दे दी गई है।

भारतीय नागरिकता पाना चाहते हैं 7306 पाकिस्तानी नागरिक

» भारतीय नागरिक बनने के लिए चीन समेत विभिन्न देशों के दस हजार से ज्यादा नागरिकों ने किया आवेदन

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए 10,635 ने विदेशी नागरिकों ने आवेदन किया है, जिसमें 70 फीसदी से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता पाने का इंतजार है।

यह जानकारी संसद में गृह मंत्रालय ने देते हुए बताया कि 7306 पाकिस्तानी भारतीय नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय नागरिकता के लिए लंबित लगभग 70 प्रतिशत आवेदन पाकिस्तानियों के हैं।

बुधवार को संसद सदस्य अब्दुल वहाब द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने कहा कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले 10,635 आवेदकों में से 14 दिसंबर, 2021 तक, 7,306 पाकिस्तान से थे।

चीन के 10 लोगों ने मांगी भारत की नागरिकता

राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब ने भारत सरकार से पूछा था कि वर्तमान में भारतीय नागरिकता पाने के लिए, कितने आवेदन आए हैं और वे किस देश से हैं। इन सवालों के जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने बताया कि अफगानिस्तान से 1,152 आवेदन लंबित हैं, इसके बाद 428 राज्यविहिन (जिसे कोई देश अपना नागरिक नहीं मानता) लोग हैं, श्रीलंका और यूएसए से 223, नेपाल से 189 और बांग्लादेश से 161 आवेदन पेंडिंग हैं। मंत्री ने कहा कि चीन के 10 आवेदकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था।

4177 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई

गौरतलब है कि भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति गृह मंत्रालय के पास होती है जो विस्तृत सत्यापन और जांच के बाद आवेदन को मंजूरी देती है। हालांकि इन लंबित आवेदनों के अलावा केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि वर्ष 2016 से 2020 के दौरान कुल 4177 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।

किन देशों के नागरिकों को मिली भारतीय नागरिकता

वर्ष 2016 से 2020 के दौरान भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने वाले लोगों का ब्योरा देते हुए मंत्री ने बताया, ''साल 2016 में 1106, 2017 में 817, 2018 में 628, 2019 में 987 और 2020 में 639 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।'' एक अन्य सवाल के जवाब में राय ने कहा कि वर्ष 2018 से 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों से नागरिकता हेतु कुल 8244 आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से 3117 व्यक्तियों को भारत में नागरिकता प्रदान की गई है।

यूएपीए कानून के तहत तीन साल में गिरफ्तार हुए 4690 लोग, 149 दोषी पाए गये

नई दिल्ली (आरएनएस)। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए को लेकर अक्सर सरकार पर इसके दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच सरकार ने बताया है कि पिछले 3 सालों में यूएपीए के तहत कितने केस दर्ज हुए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि यूएपीए के तहत पिछले 3 साल में 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से 149 लोग दोषी पाए गए। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, 'वर्ष 2018 में 1,421, वर्ष 2019 में 1,948 और वर्ष 2020 में 1,321 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया।' उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में 35, वर्ष 2019 में 34 और वर्ष 2020 में 80 लोगों को दोषी पाया गया। राय ने कहा कि एक विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दोषसिद्धि का पता चलता है और यह अलग-अलग फैक्टर्स जैसे कि ट्रायल की अवधि, सबूतों के मूल्यांकन, गवाहों की जांच इत्यादि पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूएपीए में ही सुरक्षा के अंतरनिहित उपायों समेत पर्याप्त संवैधानिक, संस्थागत और सांविधिक सुरक्षा के उपाय मौजूद हैं।

संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

» तय समय से पहले खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समयावधि से एक दिन पहले यानी बुधवार को ही खत्म हो गया। दोनों सदनों में बुधवार सुबह की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मौजूदा शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था और इसे 23 दिसंबर तक चलना था।

राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अखबार की खबर का हवाला देकर अयोध्या से संबंधित एक मुद्दा उठाने की कोशिश की लेकिन नायडू ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। सभापति ने खड़गे से कहा कि मुद्दे को उठाने के लिए उन्हें नोटिस देना चाहिए था।

लोकसभा में नौ विधेयक पारित- लोकसभा में इस दौरान 18 बैठकें हुई और सदन का कार्य निष्पादन 82 प्रतिशत रहा, वहीं व्यवधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय व्यर्थ गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह सत्र 29 नवंबर से शुरू हुआ और इस दौरान कुल 18 बैठकें हुई जो 83 घंटे 12 मिनट तक चलीं।%% उन्होंने बताया कि सत्र के आरंभ में सदन के तीन सदस्यों ने 29 और 30 नवंबर को शपथ ली। बिरला ने कहा कि इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य निपटाये गए और इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किये गए और 9 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान कृषि विधि निरसन विधेयक 2021, राष्ट्रीय औषध शिक्षा अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक 2021 और निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये गए।

भारत में टैक्स चोरी कर फंसी चीनी मोबाइल कंपनियां

» कई कंपनियों के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। चीनी मोबाइल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, आयकर विभाग देश भर में प्रमुख चीनी मोबाइल कंपनियों पर छापेमारी कर रहा है। आईटी विभाग ओप्पो, श्याओमी और वन प्लस सहित अन्य मोबाइल कंपनियों के यहां छापेमारी कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में चीनी मोबाइल फोन निर्माताओं से जुड़ी इकाइयों के खिलाफ छापेमारी की। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दक्षिण के कुछ राज्यों में स्थित परिसरों पर की जा रही है। मंगलवार से शुरू हुई तलाशी में इन कंपनियों के दो दर्जन से अधिक परिसर शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, इंदौर और कुछ अन्य जगहों पर छापेमारी जारी है। सूत्रों ने बताया कि इस रेड में कुछ फिनटेक कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस तलाशी में शामिल हैं

और फिलहाल इनसे आयकर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि इन कंपनियों के कुछ वितरकों और वितरण साझेदारों के खिलाफ भी छापेमारी की जा रही है।

खुफिया इनपुट मिलने पर डाली रेड - इन चीनी मोबाइल फर्मों द्वारा भारी कर चोरी के खुफिया इनपुट मिलने के बाद रेड डाली गई थी। ये कंपनियां लंबे समय से रडार पर थीं और जब आयकर विभाग को कर चोरी की पुख्ता जानकारी मिली तो इन कंपनियों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक, चल रही तलाशी के बारे में ब्योरा देना जल्दबाजी होगी लेकिन कर चोरी का सबूत देने वाले डिजिटल डेटा की पर्याप्त मात्रा पाई गई है और उन्हें जब्त कर लिया गया है।

चीनी दूरसंचार विक्रेता की पहले ही खुल चुकी है पोल- इससे पहले अगस्त में, एक चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित दूरसंचार विक्रेता, जैडटीई की तलाशी ली गई थी। कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस, विदेशी निदेशक के आवास, कंपनी सचिव के आवास, अकाउंट संभालने वाले व्यक्ति और कंपनी के कैश हैंडलर सहित जैडटीई के कुल पांच परिसरों में तलाशी ली गई। जैडटीई पर रेड के दौरान, बिक्री बिलों की तुलना में आयात बिलों की जांच से पता चला कि उपकरण के व्यापार पर लगभग 30 प्रतिशत का सकल लाभ हुआ था, लेकिन कंपनी पिछले कुछ वर्षों में भारी घाटे की बात कर रही थी।